बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 7

# कारोबार में संकट

**पहले** बैंकों के लिए शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई की बात कही गई और अब कारोबारियों की बारी है। अनिल अंबानी का कारोबारी समूह संकट से घिरा हुआ है। नरेश गोयल के हाथों से जेट एयरवेज का नियंत्रण छिनने की नौबत आ चुकी है। सुभाष चंद्रा का ज़ी समूह संकट से उबरने की जद्दोजहद में है। रुइया को अपना एक प्रमुख उपक्रम गंवाना पड़ा है और दूसरा भी हाथ से जाता दिख रहा है। कोलकाता में बीएम खेतान समूह अपने चाय बागान बेच रहा है और उसने एक कंपनी को भी बेचने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में सिंह बंधु रैनबैक्सी की अपनी विरासत को नष्ट करने के बाद एक दूसरे को नष्ट करने में लग गए हैं। लंदन में विजय माल्या किसी तरह यह प्रयास करने में लगे हुए हैं कि उन्हें आर्थर रोड की जेल में वक्त न बिताना पड़े।

भारी भरकम कर्ज वाली कंपनियों में बिकवाली का दौर जारी है। चाहे मामला हवाई अड्डे बनाने वाली दिग्गज कंपनियों जीएमआर और जीवीके का हो या वित्तीय क्षेत्र की आईएलऐंडएफएस और डीएचएफएल जैसी कंपनियों का या फिर अचल संपत्ति की डीएलएफ जैसी कंपनियों का, ये सारी कंपनियां समस्याओं से दो चार हैं। भूषण समूह की कंपनियां और लैंको आदि बहुत पहले परिदृश्य से नदारद हो चुकी हैं। अफवाह है कि वित्तीय क्षेत्र से अभी और गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं।

सामान्य समझ यह रही है कि सरकारी क्षेत्र बुरा है और निजी क्षेत्र अच्छा है। सरकारी क्षेत्र अभी भी बुरी स्थिति में है। एयर इंडिया पर गौर कीजिए, सरकारी बैंकों में 48,000 करोड़ रुपये की राशि डाली जानी है। बीते दो वर्ष में 1.57 लाख करोड़ रुपये की राशि डाली जा चुकी है। सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए राहत पैकेज जल्दी आ सकता है। परंतु अब निजी क्षेत्र का झंडा कौन बुलंद करेगा क्योंकि बैंकों की बैलेंस शीट की दिक्कतों, ऋण की कमी और अर्थव्यवस्था में धीमेपन के लिए प्रमुख तौर पर वही जिम्मेदार हैं।

संकट का शिकार होने वालों में से कई पहली पीढ़ी के कारोबारी हैं। रुइया सन 1990 के दशक में भी एक बार दिवालिया हो चुके हैं लेकिन शायद उन्होंने इससे कोई सबक नहीं सीखा। कई कंपनियां कर्ज में डूबी हैं या उन्होंने जिंस कीमतों में बदलाव और लंबी अवधि की परियोजनाओं का कमतर आकलन किया। कुछ किस्से वही पुराने हैं जहां कंपनियां डूबती रहीं और कारोबारी फलते-फूलते रहे। परंतु अब नए नियमों की बदौलत कंपनियों और उनके प्रवर्तकों की तकदीर एक दूसरे से कहीं अधिक गुंथी हुई हैं। जहां तक दूसरी या तीसरी पीढ़ी के कारोबारियों की बात है उनके कुप्रबंधन के कारण खस्ता हुई हालत का आनंद लेने वाले लोग भी मौजूद हैं।

**साप्ताहिक मंथन**

**टी. एन. नाइनन**

उनका स्थान कौन लेगा? क्या कारोबारियों की कोई नई पीढ़ी, बेहतर कारोबारी समझ या बेहतर तकदीर के साथ सामने आएगी? परंतु 100 करोड़ डॉलर की पूंजी वाली निजी कंपनियां ज्यादातर दूसरों की नकल करने वाले उद्यमी हैं जिनके पास चीन समेत दुनिया भर से फंडिंग आ रही है। टेक सेवाओं की तेजी के दौर में जो अरबपति सामने आए, उनमें से कई परोपकार का रुख कर चुके हैं। डीमार्ट के राधाकृष्णन दमानी जैसे कुछ सितारे अब भी फल-फूल रहे हैं जबकि सन फार्मा के दिलीप सांघवी जैसे सितारे फार्मा क्षेत्र के साथ ही अस्त हो गए। सुनील मित्तल दूरसंचार क्षेत्र के टैरिफ के भंवर में उलझ कर रह गए। मौजूदा परिदृश्य की एक खास बात यह है कि दूरसंचार और विमानन जैसे तेज विकसित होते क्षेत्र अधिशेष तैयार नहीं करते। शेयर बाजार भी बीते पांच साल में शिथिल रहा है।

उपभोक्ता कारोबार अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे हैं जहां इमामी, मैरिको तथा अन्य कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बजाज, महिंद्रा, पीरामल, गोदरेज और रिलायंस जैसे कुछ प्रतिष्ठित समूहों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। परंतु टाटा बमुश्किल डेढ़ कंपनियों का समूह नजर आ रहा है क्योंकि समूह की पुरानी दिग्गज कंपनियां केवल पूंजी खपाए जा रही हैं

सुजूकी आधे कार बाजार पर काबिज है, मोबाइल फोन बाजार में चीन का दबदबा है और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु बाजार में कोरियाई कंपनियां हावी हैं। ब्लैकस्टोन और केकेआर जैसे बड़े निवेशक अवसर देखकर बाजार में आए हैं। आईबीएम देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, होंडा ने हीरो को पीछे छोड़ दिया है, डिएगो ने माल्या को खरीद लिया है और दो बड़े निजी बैंक विदेशी स्वामित्व वाले हैं और एतिहाद जेट को खरीद सकती है। विदेशी कारोबारियों के बिना हम कहां नजर आएंगे?

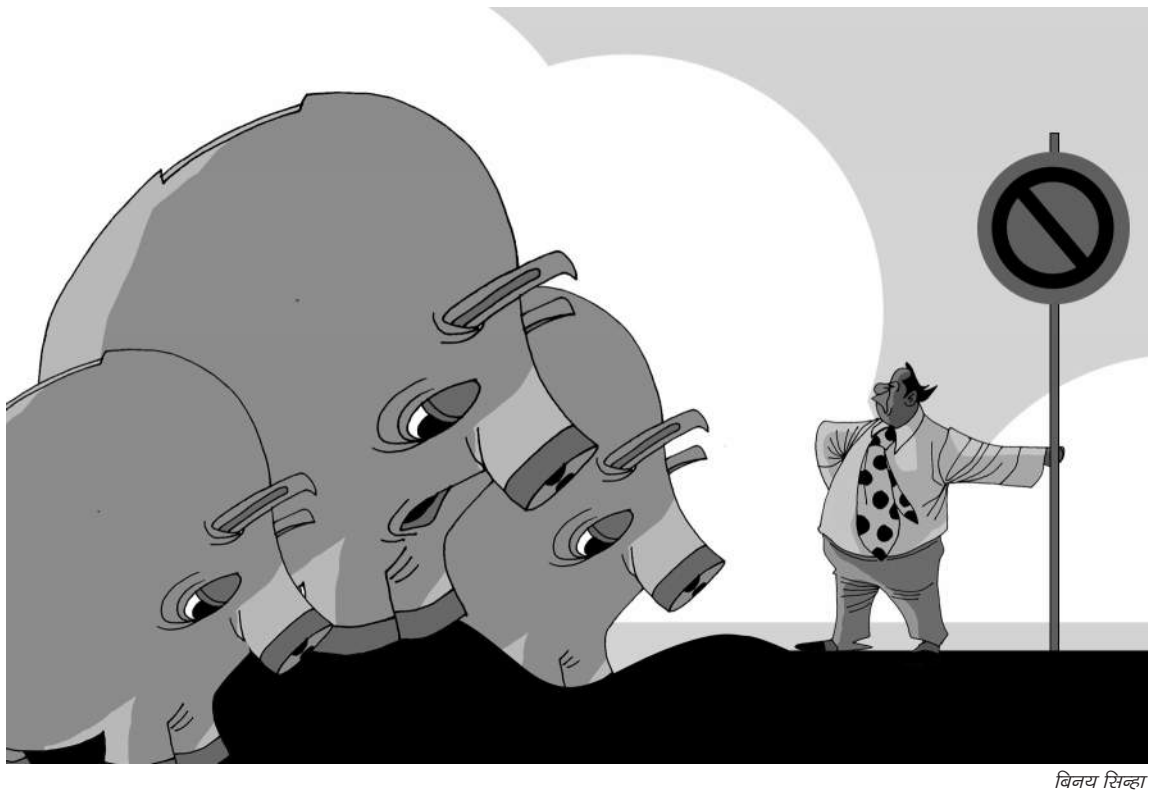

विनय सिन्हा

# बैंक ऋण की मानक दर अब तक कपोल कल्पना

**बैंक आरबीआई के सूक्ष्म प्रबंधन से प्रसन्न नहीं हैं लेकिन जब मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हो तो ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय**

आगामी अप्रैल तक देश के बैंकों को अपने फ्लोटिंग रेट वाले ऋण और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए गए ऋण को कम से कम चार मानकों में से किसी एक से जोड़ना होगा। ये मानक हैं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रीपो दर, 91 दिन और 182 दिन के ट्रेजरी बिल, ओवरनाइट मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट (माइबर) समेत कोई अन्य मानक बाजार ब्याज दर और यहां तक कि 14 दिन, एक महीने या तीन महीने की अवधि की माइबर।

यह आंशिक तौर पर एमसीएलआर अर्थात फंड आधारित ऋण दर की सीमांत लागत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा क्योंकि अन्य ऋण के लिए यह जारी रहेगी। एक बार नया मानक आने के बाद बैंकों को तब तक मानक दर को बदलने या पार करने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि किसी ऋणकर्ता के जोखिम की अवधारणा में बदलाव नहीं आता।

नियामक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था चाहता है लेकिन अधिकांश बैंक इससे नाखुश हैं। वास्तव में बैंकरों की राष्ट्रीय लॉबी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने आरबीआई को लिखा है कि एमसीएलआर प्रणाली जारी रहने दी जाए क्योंकि उक्त बाहरी कारकों में से किसी का बैंक की फंडिंग की लागत से कोई लेनादेना नहीं है। केवल सिटी बैंक को यह बेहतर लगा है और उसने आवास ऋण ब्याज दर को मार्च 2018 में तीन महीने के ट्रेजरी बिल से जोड़ दिया। ऐसा लगता है कि ऋण की अवधि तक ऋण दर में बदलाव न करने की बात ने बैंकों को अधिक प्रभावित किया है। ऐतिहासिक तौर पर अधिकांश बदलाव की व्यवस्था का फायदा उठाते रहे हैं। वे अपनी एमसीएलआर में कटौती कर देते हैं लेकिन मुनाफा बरकरार रखने के लिए ऋण दर बढ़ाए रखते हैं।

एक आंतरिक अध्ययन, जिसके आधार पर आरबीआई नई व्यवस्था पेश कर रहा है, उसने वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दर तय करने में अपारदर्शी तरीके अपनाने के लिए आड़े हाथों लिया। सन 1990 के दशक में देश के बैंकों ने अपनी प्राथमिक ऋण दर (पीएलआर) का खुलासा करना शुरू किया। यह वह ब्याज है जो सबसे उपयुक्त कर्जदारों से वसूली जाती है। सन 2003 में मानक पीएलआर पेश की गई। किसी बैंक को उससे कम दर पर ऋण देने की इजाजत नहीं थी। चूंकि कुछ ही दर इससे जुड़ी थीं इसलिए बैंक इस दर को कृत्रिम रूप से ऊंचे स्तर पर रखते और अपने अधिकांश कर्जदारों से उससे कम दर पर ऋण की वसूली करते।

सन 2010 में इसकी जगह आधार दर ने ले ली जो अब किसी भी कर्ज के लिए न्यूनतम दर थी। बैंक अब कर्जदारों के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर इसे तय करते। फंड की लागत, बकाया, कथित नकद आरक्षित अनुपात और फंसे कर्ज का स्तर पर विचार करके आधार दर तय की जाती। आधार दर और वास्तविक ऋण के बीच के दायरे पर कोई अंकुश नहीं था। एमसीएलआर व्यवस्था 2016 में लागू की गई और सीमांत लागत का आकलन किया जाने लगा।

नए कर्ज पर ब्याज दर का पारेषण एमसीएलआर में बेहतर रहा लेकिन बकाया कर्ज के मामले में हालात जस के तस रहे। बैंक नए ग्राहकों को तो कम दर पर आकर्षित करते लेकिन पुराने ग्राहकों को लाभ नहीं दिया जाता। मौद्रिक नीति सख्ती के वक्त दरों में इजाफा करने में भी बैंक देर नहीं करते।

आरबीआई ने अध्ययन में पाया कि बैंक आधार दर और एमसीएलआर के आकलन में छेड़छाड़ करके आधार दर को बढ़ाए रखते। इसके अलावा बैंकों द्वारा दरों के निर्धारण में भी अपेक्षित पारदर्शिता देखने को नहीं मिलती थी।

सवाल यह है कि नया मानक क्या होना चाहिए? साफ कहें तो आरबीआई द्वारा सुझाए गए चारों मानकों में से कोई उपयुक्त नहीं है क्योंकि देश के बैंक ऋण परिसंपत्तियां अपने जमा से तैयार करते हैं, वे नियामक अथवा बाजार के ऋण के माध्यम से ऐसा नहीं करते। निश्चित तौर पर वे आरबीआई की रीपो विंडो से उधार ले सकते हैं लेकिन इसकी राशि उनकी शुद्ध मांग के एक चौथाई प्रतिशत तक सीमित है।

उनकी फंड की लागत भी ट्रेजरी बिल प्रतिफल पर निर्भर नहीं है, जोकि व्यवस्था में मौजूद नकदी तथा अल्पावधि के मार्ग के जरिये ली जाने वाली सरकारी उधारी पर निर्भर करती है। इसमें तथाकथित नकदी प्रबंधन बिल भी शामिल हैं। इसके अलावा माइबर की विश्वसनीयता भी लाइबर या लंदन इंटरबैंक की पेशकश वाली दर जैसी नहीं है। लाइबर बैंकों द्वारा असुरक्षित फंड को दी जाने वाली उधार पर निर्भर होता है। बैंक ये उधारी लंदन इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को देते हैं।

बैंक जिस दर पर आरबीआई से उधारी लेते हैं, वह भी बैंकों के लिए बेहतर उधारी मानक हो सकती है। इसके माध्यम से बैंक रीपो की तुलना में कहीं अधिक नकदी उधार ले सकते हैं। देश के बैंकों ने जहां फ्लोटिंग दर वाले ऋणों की राह चुन ली है लेकिन फ्लोटिंग रेट पर जमा को स्वीकार करने वाले लोग देश में अब भी काफी कम हैं। मुद्रास्फीति से संबद्ध बॉन्ड की बिक्री भी अच्छी तरह नहीं हो पा रही है। सरकार की उच्च दर और कर बचत वाली अल्प बचत योजनाएं तथा कर बचत वाले म्युचुअल फंड भी जमाकर्ताओं को फ्लोटिंग दर वाले जमा की ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं।

बैंक ऋण के लिए सही मानक तय करना अभी भी कल्पना का विषय ही है। परंतु बैंकों द्वारा किए जाने वाले दर के विस्तार पर गौर किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के ऋण को एक ही मानक से जोड़ दिया जाना चाहिए। विकसित बाजार आमतौर पर दो मानक दरें रखते हैं। इनमें से एक खुदरा ऋण के लिए होती है तो दूसरी कॉर्पोरेट ऋण के लिए। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्राथमिक दर फेडरल रिजर्व की दर से ऊंची होती है और वही सभी उपभोक्ता और खुदरा ऋण के लिए मानक दर होती है। वहीं लाइबर को सभी कॉर्पोरेट ऋण के लिए संदर्भ बिंदु माना जाता है।

बैंक आरबीआई द्वारा सूक्ष्म प्रबंधन किए जाने से प्रसन्न नहीं हैं लेकिन जब मुक्त बाजार भी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है तो ऐसा करना आवश्यक है। उद्योग जगत को बैंक बचत दर के मुक्त होने के बाद की स्वतंत्रता हासिल करने में काफी वक्त लगा। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना देश के बैंकों की रुचि का विषय कभी नहीं रहा।

*(लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड में सलाहकार संपादक और जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं।)*

# नई लोकसभा में कई पुराने सदस्य नहीं आएंगे नजर

**लोकसभा** का कार्यकाल पूरा होने पर सदन के अध्यक्ष को धन्यवाद देने की परंपरा का निर्वाह करने के दौरान दिए जाने वाले सांसदों के भाषण हमेशा भावनाओं से भरपूर एवं धारदार होते हैं। मर्मस्पर्शी होने की वजह यह है कि तमाम सदस्य एक-दूसरे के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए साथ छूटने की वेदना जाहिर करते हैं। उनके भाषण धारदार होने की वजह यह है कि इस मौके पर नेता ऐसी बातें कह जाते हैं जो वे किसी अन्य मंच पर नहीं कह सकते हैं।

इस बार दिए गए धन्यवाद भाषण भी कोई अलग नहीं थे। मौजूदा लोकसभा के अंतिम कार्य दिवस पर एच डी देवेगौड़ा ने सार्वजनिक तौर पर उन दिनों को याद किया जब वह विदेशी मूल की होने के कारण सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते थे। उस समय सोनिया सदन में ही मौजूद थीं। हालांकि देवेगौड़ा ने यह माना कि उनके लिए अब यह कोई मसला नहीं रह गया है क्योंकि वह सोनिया को प्रधानमंत्री बनाने की मांग का खुद ही समर्थन कर चुके हैं। (इस दौरान सोनिया ने अपनी आदत के उलट हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थीं।)

देवेगौड़ा ने कहा कि वह सदन में 29 साल व्यतीत कर चुके हैं और लोकसभा में यह उनका अंतिम भाषण होगा। भले ही उनकी पार्टी कर्नाटक में भाजपा का मुखर विरोध कर रही है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते समय वह भावुक नजर आए।

इसी तरह मुलायम सिंह यादव ने भी प्रधानमंत्री के चुनाव जीतने और दोबारा सरकार बनाने की उम्मीद जताने वाला भाषण दिया। (इस पर उनकी रिश्तेदार राबड़ी देवी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि मुलायम अब बुजुर्ग हो चुके हैं और बोलने पर उनका काबू नहीं रह गया है)।

मोदी ने अपने भाषण में मुलायम का खास जिक्र करते हुए उनके स्नेह के लिए आभार जताया। इस तरह नई लोकसभा को लेकर चर्चा तेज होने के

**सियासी हलचल**

आदिति फडणीस

बीच मौजूदा लोकसभा को अलविदा कहा गया।

हालांकि मौजूदा लोकसभा के उन सदस्यों को निजी तौर पर विदाई नहीं दी जा सकी जो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। सुषमा स्वराज अटल सरकार के समय संसदीय कार्य मंत्री रहने के दौरान विपक्षी दलों की चहेती नेता होती थीं। एक बार अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सुषमा की पुरजोर तारीफ करते हुए कहा था कि वह देश की सर्वश्रेष्ठ संसदीय कार्य मंत्री रही हैं।

सोमनाथ के इस बयान से उनकी मार्क्सवादी पार्टी को काफी कोफ्त भी हुई थी। मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनने के बाद जब सुषमा पर ललित मोदी के लिए लॉबिइंग करने के आरोप लगने लगे थे तो मुलायम ने उनका बचाव भी किया था। यह सच है कि इस सरकार में सुषमा को विदेश मंत्री बनाकर किनारे कर दिया गया है जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय कई मुद्दों पर विदेश सचिव के मार्फत लगातार खुद संपर्क में बना रहा।

झांसी से सांसद उमा भारती ने राजनीति से संन्यास लेने से तो मना किया है लेकिन स्वास्थ्य कारणों से अगला चुनाव न लड़ने की बात कही है। उनके इस फैसले में प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले की बड़ी भूमिका हो सकती है जिसके तहत उनसे गंगा पुनरुद्धार का दायित्व वापस ले लिया गया था। उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल के अंतिम पुनर्गठन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं की थी। बेलाग अंदाज में अपनी बात रखने के लिए मशहूर उमा ने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अपने एक पार्टी सहयोगी के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी की थी, जिससे पार्टी के भीतर बहुत लोग नाखुश हो गए थे। उनमें से कुछ लोगों ने उमा को अब तक उस दिन के बयान के लिए माफ नहीं किया है।

गढ़वाल से सांसद मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी भी अगली लोकसभा में नहीं नजर आएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राजमार्गों के विस्तार का जिम्मा संभाल चुके खंडूड़ी को रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से कार्यकाल पूरा होने के तीन महीने पहले ही हटा दिया गया। शायद इस अपमान के अहसास या फिर 'बस, बहुत हो गया' के भाव ने ही उन्हें चुनाव से दूर रहने को कहा है।

उत्तराखंड से ही एक और सांसद भगत सिंह कोश्यारी भी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी तरह बिहार के मधुबनी से सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने भी चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी के लिए काम करने की इच्छा जताई है।

कुछ ऐसे नेता भी हैं जो भले ही इस लोकसभा के सदस्य न रहे हों लेकिन पार्टी का दबाव पड़ने पर दोबारा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। शरद पवार को लेकर स्थिति उलझी हुई है। वह फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं और पिछली लोकसभा में महाराष्ट्र के माढा से निर्वाचित हुए थे। उनके भतीजे एवं विधायक अजित पवार ने शरद पवार से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग रखने के लिए हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं की खिंचाई की थी। उन्होंने कहा था, 'वह खुद कह चुके हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने की मांग करने वाले नारे न लगाएं।' लेकिन शरद पवार का ताजा रुख यही है कि अगर उनकी पार्टी चाहती है तो वह माढा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने अपने भतीजे के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात भी कही है।

जो भी हो, मई में नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। तब तक के लिए पुराने सदस्यों को विदाई और नए सदस्यों के स्वागत को तैयार रहें।

## कानाफूसी

### एक दूजे के लिए

शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच आम चुनाव के पहले हुए गठबंधन से दोनों दलों ने राहत की सांस ली है। परंतु इस गठबंधन की भी एक पृष्ठभूमि है। दरअसल इन दोनों दलों ने गत जनवरी माह में एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया था। उस सर्वेक्षण से यह बात निकलकर आई कि आगामी आम चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में दोनों दलों का एक साथ चुनाव लड़ना, दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस आंतरिक सर्वेक्षण में पार्टी कार्यकर्ताओं और जिला स्तर के नेतृत्व की राय शामिल की गई। सर्वेक्षण में कहा गया था कि अगर दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो उनका दो अंकों में सीट हासिल करना भी मुश्किल साबित हो सकता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सदस्य महाराष्ट्र से ही चुने जाते हैं, ऐसे में इस प्रदेश की सरकार बनाने में अहम भूमिका है। भाजपा और शिवसेना के गठबंधन में स्वाभिमानी पक्ष के राजू शेट्टी भी शामिल थे लेकिन शेट्टी अब कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का दामन थाम चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले आम चुनाव में महाराष्ट्र में इस गठबंधन को 48 में से 42 सीटों पर जीत मिली थी।

## आपका पक्ष

### लोकलुभावन वादों के लिए धन दल ही दे

सरकार ने अंतरिम बजट में पीएम किसान योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाएंगे। भाजपा जब सत्ता में आई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 रखा गया था। लेकिन भाजपा सरकार के चार साल हो गए किसानों की स्थिति में आशाजनक सुधार नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव करीब होने के कारण सरकार ने अंतरिम बजट में पीएम किसान योजना की घोषणा की थी। इससे पूर्व पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली। कांग्रेस ने चुनावी राज्यों में कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की थी और कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ

करने की घोषणा कर दी। इस तर्ज पर केंद्र सरकार किसानों को साल में 6,000 रुपये देकर सहायता प्रदान कर रही है। दो राजनीतिक दलों के बीच किसानों की लुभाने की होड़ में भले ही किसानों को इससे फायदा मिल रहा हो लेकिन यह देश की अर्थव्यवस्था तथा विकास

**पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे**

के लिए उचित नहीं है। किसानों को अनुदान तथा ऋण माफी के कारण राजस्व का एक बड़ा भाग उसमें खर्च हो जाएगा जिससे क्षेत्र के विकास के लिए राशि नहीं बचेगी। बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो सकेगा जिससे गांव, कस्बे तथा शहरों का विकास धीमा पड़ जाएगा। अत: राजनीतिक दलों द्वारा लोकलुभावन घोषणाओं पर खर्च होने वाली राशि उसी दल से ली जाए। इससे देश का राजस्व अन्य विकास कार्यों में खर्च होगा तथा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

*मोहित कुमार, नई दिल्ली*

### संगठित क्षेत्र के कामगारों को फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि की है। पहले इस पर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत थी जिसे अब 8.65 प्रतिशत कर दिया गया है। ईपीएफओ के इस कदम से संगठित क्षेत्र के कामगारों को फायदा मिलेगा क्योंकि संगठित क्षेत्र के कामगारों की भविष्य निधि इसमें जमा होती है। इससे उन कामगारों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक राशि मिलेगी। हालांकि सरकार का यह कदम आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए माना जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पूर्व सत्तारूढ़ दल भाजपा विभिन्न क्षेत्रों पर पुरजोर ध्यान दे रही है। किसानों, कामगारों तथा बेरोजगारों के लिए कई घोषणाएं भी कर चुकी है। रेलवे ने हाल में रिक्तियां निकालने की घोषणा की थी। बेरोजगारी के लिए कुछ राज्यों में बेरोजगारी भत्ता शुरू किया गया है। वहीं किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं।

*कुमार राजेश, गाजियाबाद*

**पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।**